

Talking fair trade in Delhi

- भारत 13-14 मई, 2019 को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की दूसरी मिनी-मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेगा। वैश्विक व्यापार में विकासशील और अल्प विकसित देशों के हितों पर चर्चा करने के लिए यह अनौपचारिक बैठक अमेरिका द्वारा लगाए आरोपों पर भी ध्यान केन्द्रित करेगी कि ये अर्थव्यवस्थाएं गरीब देशों के द्वारा दी गई छूट से लाभान्वित होती हैं।
- कजाकिस्तान के अस्ताना में जून 2020 के लिए निर्धारित 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक साझा एजेंडा सेट करने के लिए एक तैयारी बैठक हो सकती है। 11वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (ब्यूनस आयर्स, दिसंबर 2017) 164 डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा कई मुद्दों पर आम सहमति बनाने के प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पाया। अमेरिका ने सब्सिडी में कमी से इनकार कर दिया है और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए एक स्थायी समाधान खोजने के लिए अपनी प्रतिबद्धता वापस ले ली है।
- विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए यह एक प्रमुख मुद्दा है। वास्तव में, गतिरोध ने कई व्यापार विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या यह विश्व व्यापार संगठन के अंत की शुरुआत है?
- मंत्रिस्तरीय बैठकों के पहले के परिणामों के बावजूद दिल्ली की बैठक में विश्व व्यापार संगठन को पुनर्वित्त करने के लिए मंच प्रदान करने की उम्मीद जगी है। बैठक के तहत ज्वलंत मुद्दे संरक्षणवादी उपायों, डिजिटल व्यापार, मत्स्य पालन, सब्सिडी, पर्यावरण के सामान, मानकीकरण, स्वच्छता और कृषि संबंधी उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित होंगे, और अन्य मामले मुख्य रूप से निवेश सुविधा के लिए बातचीत और समझौते के लिए चर्चा की उम्मीद हैं। एकपक्षीय दृष्टिकोण से बहुपक्षीय उपागम की ओर बढ़ते हुए सदस्यगण WTO की अनुलंघनीयता एवं असमर्थता को भी सुनिश्चित कर सकते हैं, इसलिए, बातचीत के परिणामस्वरूप नीतियों को लागू करने के लिए, मुख्य रूप से आपसी समझौते तथा समय के लिए यह अपरिहार्य है।
- उल्लेखनीय है कि विश्व व्यापार संगठन ने टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते को बदल दिया है, 1980 के दशक के अंत में और फिर 2017 में कृषि व्यापार वार्ताओं के मुद्दे पर गतिरोध, कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अपने यहां कृषि व्यवस्था को अनुशासित करने के लिए विकसित देशों (यूरोपीय संघ और अमेरिका) और विकासशील देशों (मलेशिया, ब्राजील और भारत) के बीच मतभेद जारी हैं, जिससे विश्व व्यापार संगठन के व्यापक विकास के एजेंडे को खतरा है।
- सदस्य देश एकपक्षीय कार्रवाई और डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान प्रणाली के एक प्रस्ताव पर संशोधन चाहता है। उम्मीद है कि बैठक में वैश्विक ज्ञान जैसे कॉर्पोरेट मानदंड से संरक्षण, सब्सिडी, ई-कॉमर्स के संदर्भ से सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष और अंतर उपचार की निरंतरता के वैश्विक मानदंडों जैसे मुद्दों पर नीतिगत मार्गदर्शन हो सकता है।

- बाजार की विफलता और अन्य अनिश्चिता की स्थिति में विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को समर्थन देने के कारण व्यापार से विकासशील देशों की उम्मीदें भी बंध जाती हैं। सब्सिडी के माध्यम से समर्थन, कमोडिटी की कीमतों में विकृतियां लाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का अनुमान है कि विकसित राष्ट्रों द्वारा सब्सिडी की मात्रा \$ 300 से \$ 325 बिलियन प्रतिवर्ष तक अलग-अलग हो सकती है, जो कि विकासशील देशों के लिए अनुमान से कहीं अधिक है। यह व्यापार वार्ता में विवाद का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि अमेरिका, यूरोप और जापान में किसानों को सब्सिडी जारी रखने, अधिकारियों और सांसदों को प्रभावित करने, के लिए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया है।
- चिंता का एक और बिंदु यह है कि विकसित देशों ने कड़े नॉन-टैरिफ उपायो (NTM) को बनाया और कार्यान्वित किया है, जो गरीब देश समस्याओं का सामना कर रहे हैं एवं जो निर्यात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, कई एनटीएम के साथ अधिग्रहण की लागत निर्यातकों के बीच विषम है क्योंकि अनुपालन उत्पादन सुविधाओं, तकनीकी जानकारी और बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है। इसलिए विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं और शायद ही कृषि, वस्त्र और सहायक जैसे तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों से लाभ उठाते हैं।

गतिरोध को समाप्त करना

महत्वपूर्ण रूप से, यदि विकासशील और कम विकसित देशों के हितों को संबोधित नहीं किया जाता है, तो एक जैसा होने के बावजूद शब्दजाल के रूप में दृढ़वार्ता वर्तमान एवं भविष्य में तुच्छ हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, 10वीं मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (नैरोबी, दिसंबर 2015) में कृषि व्यापार पर जोर दिया गया। लेकिन यह भारत और अफ्रीका सहित अधिकांश कृषि अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक झटका था, जब विकसित देशों ने गरीबों के लिए बनाए गए खाद्य सुरक्षा के अपने मॉडल को सीधे चुनौती दी। परिणाम ने स्पष्ट रूप से एक बहुपक्षीय वार्ता प्रणाली की बाधाओं को दिखाया जहां समझौता और समझौता नहीं करने की आवश्यकता प्रबल होती है और किसी भी सदस्य को, चाहे वह कितना भी कम महत्वपूर्ण हो, सभी मुद्दों पर किसी भी प्रगति को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। जिस व्यापक और भिन्न हितों वाले सदस्यों ने प्रक्रिया को रोक दिया है और मुद्दों पर अच्छे विश्वास में बातचीत करने से इनकार कर दिया है।

2017 में ब्यूनस आयर्स में एक समान परिणाम था। विकसित देशों ने नव उदित मुद्दों को निवेश की सुविधा, ई-कॉमर्स के लिए नियम, लिंग समानता और मत्स्य पालन पर सब्सिडी जैसे क्षेत्रों को तैयार करने के लिए गठबंधन तैयार किया, उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स 1998 में जिनेवा में दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के बाद एक मुद्दा था। यह ई-कॉमर्स और मौजूदा व्यवस्था के बीच संबंधों पर ध्यान देने के साथ वैश्विक ई-कॉमर्स की जांच के लिए एक कार्यक्रम स्थापित करने के लिए समझौते पर सहमत हुआ था। इसने एक बड़ी बहस पैदा की।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- विकसित और विकासशील देशों के मध्य उत्पन्न व्यापारिक गतिरोध को समाप्त करने में WTO असमर्थ प्रतीत हो रहा है तथा अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। उपर्युक्त कथन की विवेचना कीजिए।



